



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 1976/ज्येष्ठ 5, 1898

No. 247]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 1976/JYAISTHA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF LABOUR ORDER

*New Delhi, the 26th May 1976*

S.O. 368(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in any of the Railway Services in India would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strike in the said Railway services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits any strike in connection with any industrial dispute in the Railway Services in India for a period of six months with effect from the 26th May, 1976.

[No. F S. 42011/4/76/DIA]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

**अस सञ्चालय****आवेश**

नई दिल्ली, 26 मई, 1976.

**का० झा० 368(अ).**—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

और, यतः, भारत की रेलवे सेवाओं में से किसी एक में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, अतः उक्त रेलवे सेवाओं में हड़तालों को रोकना आवश्यक और समीचीन है।

अतः, अब, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत की रेलवे सेवाओं में किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी हड़ताल को 26 मई, 1976 से छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है।

[सं० का० एस 42011/4/76 डी आई ए]

टी० एस० शंकरन, संयुक्त सचिव।